सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 16 OCTOBER TO 22 OCTOBER 2019 • VOLUME-10 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

सोशल मीडिया से

अनमोल विचार

लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाभी ताला खोल देती है

मर्सीडीज के पैंचर टायर पर मारूती की स्टपनी लगाने की तैयारी

नैशनल हाईवे विभाग

■ जालंधर से प्रभात सूरी की विशेष रिपोर्ट

केन्द्र के परिवहन विभाग का मंत्री बड़े ज़ोर-शोर से संसद में अपने विभाग की पीठ थपथपा नहीं थकते कि हमारा विभाग देश का एकमात्र ऐसा विभाग जो वित्तीय विभाग की मदद के बगैर अपने विभाग को अपने दम पर चला रहा है और हमारे इस माडल पर विदेशों में इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। परन्तु विभाग के मंत्री को शायद यह नहीं पता कि नई दिल्ली द्वारका में नैशनल हाईवे के हैड आफिस में ए.सी. कमरों में बैठे अफसर पिछले दस साल से जालंधर-पानीपत हाईवे से गुजर रहे लोगों का करोड़ों रुपये का नुकसान जिसमें कि निर्माण के दौरान उनकी जो दुकानें बंद करनी पड़ी लाखों रुपये के तेल की बर्बादी, लाखों रुपये के वाहनों की खराबी, हजारों परिवारों के अन्नदाता की मौत इसका हिसाब-किताब की कभी अफसरों से लिया गया और इसकी रिपोर्ट भी कभी संसद में पेश की जाएगी। पीएपी-रामामंडी फ्लाईओवर पर तो एक दो घंटे की फिल्म भी बन सकती है क्योंकि दस साल में ऐसे-ऐसे वीडियों लोगों के मोबाइल में मौजूद है जिसमें कोई गाड़ी पानी में डूबी हुई और कोई ट्रक-ओवरलोडीड ट्रक पलटा पड़ा है। हास्यपद बात यह है कि 10 साल बाद इन फ्लाईओवरों को बनाने में लगा दिए गए जब इसे खोला गया तो इसमें एक फ्लाईओवर को तुरंत बंद कर दिया गया और अब इनकी खामियों को दूर करने के लिए जिलाधीश जालंधर द्वारा नैशनल हाईवे आफिसर को जालंधर कैंट की दीवार के साथ एक 3 मीटर की स्लिप रोड़ बनाने के लिए कहा गया जबकि नियमों के अनुसार कम से कम साढ़े 5 मीटर स्लिप रोड़ होना जरूरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मर्सिडीज के पैंचर टायर पर विभाग के अफसरों द्वारा मारूती की टायर स्टपनी से जुगाड़ किया जा रहा है और जालंधर के जिलाधीश द्वारा इसका ट्रायल करवाया जा रहा है और विभाग से ऐसे जोड़ की लिखित में गारंटी मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री के पर्यावरण बचाने वाले कदमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, जिसमें कि वो अपने भाषणों में बार-बार एनर्जी एफिशिएंसी की बातें करते है और नैशनल हाईवे विभाग द्वारा रामामंडी से यू टर्न मारने के लिए सफर को एक से डेढ़ किलोमीटर बढ़ाने की सोच रहे है और लाखों रुपये की रोज़ाना तेल की बर्बादी होगी और वातावरण भी प्रदूषित होगा। इन सभी वाक्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिलाधीश जालंधर डैपुटेशन पर दिल्ली जाना चाहते है और इसमें उनको कोई रूकावट ना आए इसलिए वो केन्द्र के इस विभाग के अफसरों के साथ उलझना नहीं चाहते। फिर उनके ऊपर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे है? जिलाधीश को यह बात समझनी चाहिए कि इन्फ्रास्टैकचर के प्रोजैक्टस जुगाड़ पर नहीं चलते इनके इंटरनैशनल लैवल और नैशनल लैवल पर आई.आर.सी. द्वारा नियम बनाए गए इसका पालन करवाना आपके अधिकार क्षेत्र का काम है और इसको लागू करवाने के लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जाए। अगर नैशनल हाईवे विभाग द्वारा इसमें जो भी त्रुटियां की गई है उनके ऊपर 304-ए का मुकद्दमा दर्ज करके जाँच चलाई जाए।

पुडा विभाग

कानून पसंद लोगों को तंग करना बंद करें अफसर

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

अवैध कालोनियां और अवैध बिल्डिंगों के बाबत एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पुडा विभाग द्वारा एक चहेड़ू-महेड़ू में एक सर्वे चलाया जा रहा है। जिसमें बिल्डिंग मालिकों को PAPRA ACT 1995 के अधीन नोटिस जारी किये जा रहे हैं जिसमें किसी की प्रोपर्टी का नोटिस किसी के नाम चिपकाया जा रहा है और लोगों को बड़े स्तर पर डराया धमकाया जा रहा है। इस वाक्य से पता चलता है कि पुडा विभाग अफसर कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि अब याचिका दायर होने के बाद ऐसे चुप करके बैठ गए हैं कि उनको पता ही नहीं कौन सी बिल्डिंग वैध है और कौन सी अवैध और हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए एक सर्वे चला दिया है, पर यह रिकॉर्ड तो पुडा के पास पहले ही मौजूद है की कौन सा प्लाट या बिल्डिंगे लोगों के द्वारा रेंगुलर करवाई गई है क्योंकि यह एकबारगी निपटान पालिसी 2013 में पहली बार अकाली-भाजपा सरकार द्वारा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए लाई गई थी और सारा पालिसी का पैसा इस शर्त पर इकट्ठा किया गया था कि उस पैसे से कॉलोनी की जरूरतों को पूरा किया जाएगा पर न तो कोई सुधार करवाया और न ही इसके होने की संभावना है और उल्टा पुडा के भ्रष्टाचारी अफसर कमाई का नया साधन बना रहें और लोगों को फोन कर के पुडा विभाग में पेश होने के नोटिस निकाल रहे हैं पुडा के उच्चाधिकारियों की इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि कानून पसंद लोगों को निचले स्तर के अफसर तंग परेशान ना करें और अपने स्तर पर मौजूद रिकॉर्ड से जाँच करें कि कौन सी बिल्डिंग वैध है या अवैध है।

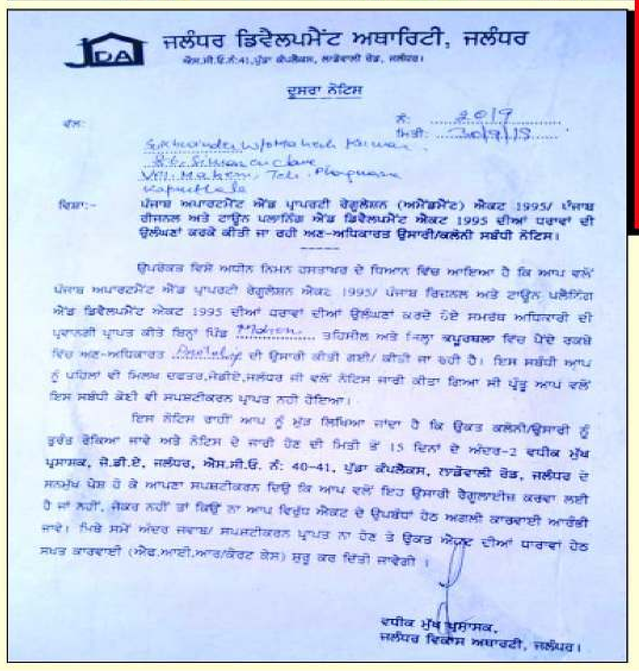
ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ

ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 1995/ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ/ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ।

किसी की प्रोपर्टी का नोटिस किसी के नाम चिपकाया जा रहा है और लोगों को बड़े स्तर पर डराया धमकाया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, बच्चों के बैग का वजन कम करने का लागू करें दिशानिर्देश

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करने संबंधी दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने बच्चों को भारी बैग के बोझ से बचाने के लिए 2016 में दिशानिर्देश जारी किए थे। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, '' दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए हमने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। भारी बैग स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। '' अधिकारी ने कहा,'' भारी स्कूल बैग का बढ़ते बच्चों पर एक गंभीर, प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव होता है जो उनके 'वर्टिब्रल कॉलम' और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

इसके अलावा दो या बहुमंजिला इमारतों वाले स्कूलों, जहां बच्चों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, ऐसे में भारी बैग समस्या और बढ़ा सकते हैं। यह घबराहट का भी एक कारण हैं।'' दिशा-निर्देशों को इस बात पर गौर कर तैयार किया गया था कि पाठ्यपुस्तक, गाइड, होमवर्क और क्लासवर्क नोटबुक, किसी न किसी काम की नोटबुक, पानी की बोतलें, लंच बॉक्स स्कूल बैग का भार बढ़ा देते हैं। कभी कभी स्कूल बैग भी भारी होते हैं।

आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन को हिरासत में लिया गया

■ श्रीनगर/न्यूज नेटवर्क

पुलिस ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की बेटी और बहन समेत छह महिलाओं को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि ये महिलाएं जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थीं। महिला प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहीं अब्दुल्ला की बहन सुरैया और उनकी बेटी साफिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

बांह पर काली पट्टी बांधकर तख्तियां पकड़े प्रदर्शन कर रहीं इन महिलाओं को पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका और शांतिपूर्वक लौट जाने के लिए कहा। महिलाओं ने जाने से मना किया और प्रदर्शन जारी रखते हुए धरने पर बैठ गईं। महिला सीआरपीएफ जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहनों में बैठाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कवरेज के लिए आए मीडिया को बयान वितरित करने से रोकने का प्रयास भी किया। बयान में कहा गया है

''हम कश्मीर की महिलाओं ने भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाए जाने तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एकतरफा फैसले को अस्वीकार कर दिया है।

नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए महिलाओं ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से धोखा और अपमान मिला है। उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विसैन्यीकरण की भी मांग की। बयान में यह भी कहा गया है '' हम कश्मीर में झूठे एवं गुमराह करने वाले प्रचार के लिए राष्ट्रीय मीडिया के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं।''

ट्विटर

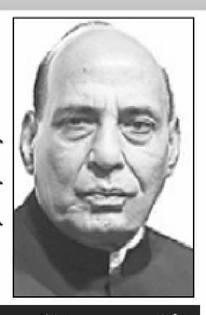

कश्मीर में सेना को आतंकी वारदात की पूरी जानकारी है। आतंकी जैसे ही मांद से निकलेंगे ढेर कर दिए जाएंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

उक्ति

"किसी को हराना बहुत आसान काम है। यह जरा सी तिकड़म से हो जाता है, लेकिन किसी हारते हुए को जिताना कठिन होता है। यह काम केवल महान लोग कर पाते हैं।

-चाणक्य

दखल

भारत में कैंसर का बढ़ता कहर

दरअसल, हमारे यहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा इस कदर कमजोर है कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां समय पर पहचान में नहीं आ पातीं और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की नाहक ही जान चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पतालों का रुख करता भी है तो वहां का महंगा इलाज उसे लाचार बना देता है। कैंसर की बीमारी की रोकथाम का इलाज सिर्फ समझ और जागरूकता है।

एक समय था जब कैंसर से पीड़ित मरीजों के मामले कभी-कभार सुनने में आते थे और यह लोगों के चौंकने का मामला होता था। पर आज अक्सर लोगों को उनके संपर्क के किसी व्यक्ति के कैंसर से पीड़ित होने और कई बार उनकी मौत तक की खबरें सुननी पड़ती हैं। जाहिर है, कैंसर के इस तरह पांव फैलाने के पीछे एक बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खानपान से लेकर समूची जीवनशैली में आए बदलाव हैं। लेकिन इस समूचे मसले पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यह जानलेवा रोग बहुत तेजी से बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। एक खबर के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग तीन लाख बच्चे इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इनमें से 78 हजार यानी करीब एक चौथाई से ज्यादा बच्चों की मौत अकेले भारत में होती है। यह आंकड़ा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का कैंसर की चपेट में आना एक बड़ी चेतावनी है कि आने वाली पीढ़ियों पर कैंसर की भयावह मार पड़ सकती है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि यह रोग खानपान और जीवनशैली की वजह से उभरता है और आमतौर पर रोग-प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने की वजह से ही किसी व्यक्ति के शरीर में घर बनाता है। तो क्या हमारे समाज में लोग अपने बच्चों के जीवन को इस जोखिम में छे? रहे हैं जिसमें वे इस रोग से बचाव के प्रति लापरवाही बरतें? निश्चित रूप से कैंसर के लिए वंशानुगत अथवा अनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की खाने-पीने चीजें बच्चों की आदत में शुमार होती गई हैं, वे उनके शरीर के पोषण की स्थिति को कमजोर करती हैं और उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा संरक्षण में रहने वाला कोई भी बच्चा आसानी से किसी बीमारी और यहां तक कि कुछ स्थितियों में कैंसर जैसे घातक रोग की चपेट में आ जाता है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा समय तक भी इसका कोई कारगर और सुलभ इलाज नहीं ढूंढ़ा जा सका है। फिर भी, अगर शुरुआती दौर में कैंसर का पता चल जाता है तो ज्यादातर मामलों में उससे निजात पाई जा सकती है।

दरअसल, हमारे यहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा इस कदर कमजोर है कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां समय पर पहचान में नहीं आ पातीं और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की नाहक ही जान चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पतालों का रुख करता भी है तो वहां का महंगा इलाज उसे लाचार बना देता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कैंसर पीड़ित बच्चों के अस्पताल और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने की दर केवल 15 फीसद है। दूसरी ओर, विकसित देशों में कैंसर से पीड़ित 80 फीसद बच्चे इस रोग के इलाज के दौरान ठीक हो जाते हैं, जबकि भारत में डॉक्टर कैंसर से पीड़ित केवल 30 फीसद बच्चे ही बचा पाते हैं। जाहिर है, परिवारों में बच्चों के खानपान, जीवनशैली में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के समांतर गरीबी और जागरूकता के अभाव को दूर किए बिना इस रोक की मारक क्षमता से लड़ पाना मुश्किल बना रहेगा। सवाल है कि जब कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से इस रोग की समय पर पहचान कर पाना ही मुश्किल बना हुआ है, तब उसके इलाज को लेकर कितना आश्वस्त हुआ जा सकता है!

भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कैंसर तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन भारत में यह कुछ ज्यादा ही खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। भारत में कैंसर की स्थिति को लेकर किए गए एक ताजा अध्ययन में बताया गया है कि यहां प्रत्येक 20 वर्ष में इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा आबादी वाले आठ राज्यों में है। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में इसी माह प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि भारतीय आर्युवेदों और पांडुलिपियों में भी कैंसर जैसी बीमारियों और उपचार का उल्लेख मिलता है। मतलब कैंसर सदियों पुरानी बीमारी है। अर्थवेद समेत कई भारतीय ग्रंथों में भी इसी तरह की बीमारी का जिक्र करते हुए बचाव के लक्षण बताए गए हैं। वर्ष 1860 से 1910 के बीच इंडियन मेडिकल सर्विस के डॉक्टरों द्वारा पूरे भारत में कई ऑडिट्स किए गए और कैंसर संबंधी मामलों का ब्यौरा प्रकाशि किया गया था। 19वीं सदी में पश्चिमी दवाओं की स्वीकार्यता बढ़ने के बाद कैंसर की जांच शुरू हुई।

वर्ष 1917 से 1932 के बीच भी भारतीय डॉक्टरों द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट व क्लीनिकल डाटा का अध्ययन किया गया, इसमें पता चला कि अधेड़ आयु और बुजुर्ग अवस्था में कैंसर से मौत के मामले सामान्य होते जा रहे हैं। भारत में कैंसर की स्थिति पर यह अध्ययन कोलकाता स्थित टाटा मेडिकल सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव डिजीस के मोहनदास के. मल्लाथ और लंदन स्थित किंग्स कॉलेज के शोधछात्र रॉबर्ट डी स्मिथ ने मिलकर किया है। इसमें बताया गया है कि भारत में प्रत्येक 20 वर्ष में कैंसर के मामले दोगुने हो रहे हैं। कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान राज्य में है। इसकी वजह ये है कि ये राज्य महामारी के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जिन आठ राज्यों में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां इसके इलाज की सुविधाएं न के बराबर हैं। भारतीय शोधकर्ता मल्लाथ के अनुसार अगर इन राज्यों की मौजूदा स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो स्थिति हमारी उम्मीदों से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इन राज्यों के अलावा भी पूरे देश में कैंसर के इलाज के आधारभूत ढांचे का भारी अभाव है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब होने की वजह से वहां पर्याप्त और बेहतर इलाज संभव नहीं है। निजी अस्पतालों में जो इलाज की सुविधाएं मौजूद भी हैं, वो बहुत महंगी हैं। बहुत से मामलों में देखा गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार भी निजी अस्पताल में इस बीमारी का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है।

कैंसर पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक जीवनशैली की देन है। अध्ययन में कैंसर के लिए इंसानों की बढ़ती औसत आयु को वजह बताया गया है। पहले भी कैंसर पर रिसर्च करने वालों ने बढ़ती उम्र को ही कैंसर की वजह मानी है। अध्ययन में कहा गया है कि कैंसर से बचाव के उपाय अपनाने के बाद भी देश में कैंसर के मामले बढ़ेंगे। इसकी वजह आम लोगों की आयु बढ़ना है। मसलन अगर सरकार तंबाकू उत्पाद को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देती है तो लोगों की औसत आयु तकरीबन 10 वर्ष और बढ़ सकती है। इससे महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामले तो और बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी मुख्य वजह ही लंबी आयु है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कैंसर की नियमित जांच, शुरुआती चरण में पहचान और इलाज की सुविधा शामिल हो। बहुत से विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सरकार को निजी अस्पतालों के कैंसर केयर प्रोग्राम पर रोक लगा देनी चाहिए। निजी क्षेत्र में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा और बहुत कम लोग ही ये खर्च उठा सकते हैं।

विशेष संपादकीय

कश्मीर में चिंता बढ़ा रहे आतंकी

जम्मू-कश्मीर से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी नहीं हो रही हो। इससे सीमाई इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस साल पाकिस्तान ने दो हजार पचास बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। जाहिर है, पाक फौज भारत को उकसाने के लिए गोलीबारी, मोर्टारों से हमले और आतंकियों की घुसपैठ कराने जैसी रणनीति पर काम कर रही है। भारत और पाक के बीच 2003 में संघर्षविराम समझौता हुआ था और दोनों देशों ने यह तय किया था कि उकसावे के लिए कोई भी पक्ष अपनी ओर से पहले गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन सीमापार से होने वाली अनवरत गोलीबारी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान के लिए इस समझौते का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लिए संघर्षविराम समझौता एक तरह से बेमानी है। कई बार तो सीमाई इलाकों में हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को गांव छोड़ने तक को मजबूर होना पड़ जाता है और सुरक्षित ठिकाने तक तलाशने पड़ते हैं। इस साल अब तक भारतीय सीमा में स्थित गांवों में 21 लोग पाकिस्तानी फौज की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। संघर्षविराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि बौखलाया हुआ पाक कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए किस सीमा तक जा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीमा पर लगातार गोलीबारी के पीछे सबसे बड़ा मकसद भारत के सैन्य बलों का ध्यान बंटा कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाना है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज नियंत्रण रेखा और सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाए है। यों भी, पाकिस्तान भारत में हर तरफ से आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। पिछले दिनों ही पाक अधिकृत कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा से तीस किमी पहले पाकिस्तान ने दो हजार सैनिक और पांच सौ प्रशिक्षित कमांडो तैनात किए हैं। इनकी मदद से आतंकियों को घाटी में घुसपैठ कराने की योजना है। समुद्र के रास्ते भी आतंकियों की भारत में घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में भी पाकिस्तान सेना ने विशेष बलों को तैनात किया है, ताकि उस रास्ते भी भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और संवेदनशील इलाका जम्मू-कश्मीर से लगती सीमा है। सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकी हैं। घाटी में करीब ढाई सौ आतंकी मौजूद हैं। सेना और पुलिस ने भी इस बात को माना है कि अकेले श्रीनगर शहर में चौबीस से ज्यादा आतंकी हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा में श्रीनगर के राज बाग, जवाहर नगर, लाल चौक सहित कई इलाकों में आतंकी लोगों और दुकानदारों को धमका रहे हैं।

औद्योगिक कॉरिडोर तय करेगा विकास

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यानी डीएमआईसी एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों से गुजरेगी। ऐसे में न केवल इन राज्यों बल्कि आसपास के कुछ अन्य राज्यों के पास भी यह अवसर होगा कि वे इस कॉरिडोर से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकें। यह अवसर केवल उद्योगपतियों और कंपनियों के लिए नहीं बल्कि इन राज्यों के लोगों के लिए भी हैं। उनके लिए कॉरिडोर के आसपास विकसित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप में रोजगार के अपार अवसर होंगे। एक छोटे-मोटे शहर की तरह विकसित होने वाली इन औद्योगिक टाउनशिप में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना तय है। मध्य प्रदेश विशालकाय इंडस्ट्रियल टाउनशिप परियोजना का हिस्सा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस परियोजना को लेकर जितने उत्साहित हैं, उसे देखकर प्रदेश की जनता के मन में भी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। डीएमआईसी की बात करें तो 9000 करोड़ डॉलर से विकसित किया जा रहा यह कॉरिडोर पूरे देश के विकास के लिए बहुत मायने रखता है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा लेकिन मध्यप्र देश के आर्थिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका होने वाली है। 1483 किलोमीटर लंबाई वाले इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में मध्यप्रदेश की 372 वर्ग किमी भू-भाग वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बस रही है। यह बहुत बड़ा इलाका है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की आर्थिक तस्वीर में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक सड़क-हवाई अथवा रेल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (आगरा-मुंबई) इसे सड़क मार्ग से जोड़ता है जबकि करीब स्थित इंदौर शहर इसे रेल और हवाई संपर्क प्रदान करता है। इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में मप्र की जो एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है वह निवेश तो लाएगी ही साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के बेशुमार मौके देगी। टाउनशिप पीथमपुरधार- महू औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश का नीमच-नयागांव व रतलाम-नागदा क्षेत्र भी डीएमआईसी के निवेश और औद्योगिक विकास क्षेत्र में आते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ निरंतर निवेश की आवश्यकता और औद्योगिक विकास पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में यह टाउनशिप उम्मीदों को पूरा करने का अहम जरिया बन सकती है। देशव्यापी स्तर पर देखें तो यह कॉरिडोर रोड, रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह स्वाभाविक रूप से औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने का काम करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश की कारोबारी राजधानी मुंबई तक की दूरी तय करने वाला यह कॉरिडोर देश के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों से गुजरेगा। इस कॉरिडोर के दोनों ओर निवेशकों के लिए निवेश के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होंगे। कॉरिडोर में बनने वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में माल और अन्य वस्तुओं का तेजी से से अबाध परिवहन सुनिश्चित होगा। जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद एक देश-एक कर प्रणाली लागू हो चुकी है। ऐसे में कॉरिडोर के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का तेज गति से परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। यह तीव्र गति मध्यप्रदेश में बढ़ते निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में भी परिलक्षित होगी। कई और बातें हैं जो मध्यप्रदेश को निवेश केंद्र के रूप में प्रमुखता देती हैं। मध्यप्रदेश में प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है जो लैंड बैंकों के माध्यम से कारोबारियों को दी जाती है। इसके अलावा मप्र की धरती प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है। कोयले से लेकर हीरा तक, मैंगनीज से लेकर बॉक्साइट तक तमाम प्राकृतिक संसाधन मध्यप्रदेश की धरती के गर्भ में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा करती रहती है। प्रदेश कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। बिजली उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली है और जिसे वह जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों को बेचता है। प्रदेश ने कौशल विकास का भी एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। ऐसे में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी, परियोजना के पहले चरण में दूसरे सबसे बड़े भू-भाग वाली हिस्सेदारी है। मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योग लगाए जाएंगे। ये वे क्षेत्र हैं जो पहले ही तेज विकास के साथ अपनी उपयोगिता को साबित कर चुके हैं। इसके अलावा वाहन एवं वाहन कलपुर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चलते ही पीथमपुर को डेट्रॉयट कहा जाता है। प्रदेश के मु यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। करीब 10 महीने पहले पद संभालते ही उन्होंने कई घोषणाएं की थीं जो निवेशकों और कारोबारियों का उत्साह बढ़ाने वाली थीं। नए फूड पार्क और टैक्सटाइल पार्क की स्थापना, देश के जानेमाने उद्यमियों के साथ मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करना, युवाओं को नए क्षेत्रों में कौशल विकास का अवसर देना और रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना ऐसे ही कुछ कदम हैं। उ मीद की जानी चाहिये की उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आनेवाली मध्यप्रदेश की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी विकास के आयाम गढ़ेगी। मु यमंत्री कमलनाथ ने कई मौकों पर कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावना है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है। यहां पर पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से निवेश हो, जिससे आर्थिक उन्नति के साथ युवाओं को रोजगार भी मिले। मु यमंत्री कमलनाथ ने आह्वान किया कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश किया जाए। प्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगों को पूरी सुविधाएं एवं सहयोग दिया जाएगा। तकनीकी में दिन-प्रतिदिन तेजी से बदलाव आ रहा है। तकनीकी के कारण जीवनशैली भी बदल रही है। उद्योग एवं व्यवसायों को भी तकनीकी के दौर में बदलाव के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मध्यप्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। यहां की आर्थिक गतिविधि भी कृषि आधारित है। किसानों को परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक खेती की तकनीक से जोड़ने की बात पर भी जोर देना होगा। मध्यप्रदेश का आज जिस तरह का वातावरण है, उसमें कमलनाथ सरकार अपने एजेंडे में सफल होकर रहेगी।

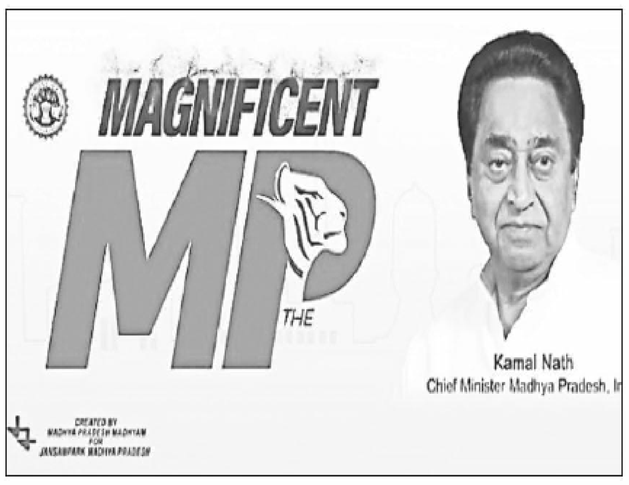

मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कारोबारी सुगमता में निरंतर सुधार हो और प्रदेश में नया निवेश आता रहे। उनका यह सोचना है कि नागरिक सेवाओं की तरह कारोबारियों की समस्याओं की सुनवाई भी जल्द से जल्द हो। मुयमंत्री कमलनाथ के 9 माह के कार्यकाल में ही मध्यप्रदेश तमाम मानकों पर देश के दूसरे प्रदेशों पर भारी पड़ रहा है।

मोदी-शी ने दिया पाक को झटका

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत की यात्रा विवादों को दरकिनार कर आगे की राह तय करने के लिहाज से बेहद सफल साबित हुई है। खास तौर पर पाकिस्तान के सबसे अहम सहयोगी माने जा रहे चीन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से कश्मीर मुद्दे पर खामोशी ओढ़ी उसे भारत की बड़ी सफलता और पाक के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जिनपिंग की यात्रा में सबसे ज्यादा कयास कश्मीर को लेकर लगाए जा रहे थे। इसके परे विश्व के दो ताकतवर नेताओं ने विवादों की छाया से बचते हुए व्यापार और परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई थी उसमें वे सफल साबित हुए। उनकी जिनपिंग से निजी केमिस्ट्री का असर दिखा। देखा जाए तो निजी रिश्ते बनाना और उसका कूटनीतिक उपयोग करना इस तरह की अनौपचारिक यात्राओं में काफी अहम होता हैं। इस लिहाज से दोनों ने भरोसा मजबूत करने के लिए बात की। मोदी-जिनपिंग ने व्यापार, निवेश और सेवा के लिए अलग तंत्र बनाने की घोषणा करके स्पष्ट संकेत दिया कि आर्थिक प्रगति और विकास का एजेंडा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि कश्मीर को लेकर भारत की संवेदनशीलता है। अगर कश्मीर का मुद्दा बैठक में उठता तो पूरी वार्ता का फोकस कश्मीर हो जाता इससे दोनों देशों के आर्थिक एजेंडे पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। भारत ने भी चीन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा है। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौती का जिक्र बातचीत में किया पर विवादों से दूर रहे। भारत के लिए चीन से रिश्तों को बेहतर बनाए रखना जरूरी है। चीन का भारत में निवेश है। वहीं भारत का भी चीन से व्यापार बढ़ रहा है। व्यापार घाटे को पाटना भारत के लिए चुनौती है। ऐसे में भारत स्पष्ट रूप से चीन के साथ सहयोग के बिंदुओं पर काम करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना का आह्वान करते हुए कहा कि द्विपक्षीय मतभेदों को आपसी सहयोग को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। शी ने कहा, हमें एक दूसरे के मूल हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। हमें उन समस्याओं का उपयुक्त ढंग से प्रबंधन और नियंत्रण करना चाहिए, जिन्हें फिलहाल सुलझाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने दोस्ताना और सहज माहौल में साझा हित के बड़े अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मोदी के साथ कई घंटों तक बातचीत करने वाले चीनी राष्ट्रपति ने विवादों को संबंधों पर प्रभाव डालने की अनुमति दिए बगैर संबंधों के निरंतर विकास के लिए छह सूत्री फार्मूले का प्रस्ताव दिया। देखा जाए तो शी जिनपिंग दो दिन भारत में रहे और इस दौरान उनका पूरा फोकस दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने में रहा। वैसे, शी की यह सोच आगे भी जारी रहे तो बेहतर है।

सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी आतंकी कश्मीर में लोगों और दुकानदारों को धमका रहे हैं। हमारी सेना को अब इनका काम तमाम करना होगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863,

All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनॉ (Renault) ने भी कमर कस ली है। रेनॉल्ट अब 2022 तक भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना चाहती है। रेनॉ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा कि कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन कथित रूप से किफायती या बड़े बाजार सेग्मेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा।

टाटा टिगोर ईवी : एक बार में चलेगी 213KM, घर में हो जाएगी चार्ज

टाटा मोटर्स ने आम ग्राहकों के लिए अधिक दूरी तक चलने में सक्षम इलेक्ट्रिक टिगोर को भारतीय बाजार में बुधवार को पेश किया। एक बार चार्ज करने पर यह कार 213 किलोमीटर चलने में सक्षम है।

इस मॉडल के तीन संस्करण बाजार में उतारे गए हैं और यह देशभर के 30 शहरों में उपलब्ध होंगे। सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 9.44 लाख रुपए से शुरू होगी। कंपनी ने कहा कि यह वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए फेम-दो योजना की पात्रता को पूरा करती है। केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलेगा, जो बैटरी कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। इससे कार की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही कार का तापमान संतुलन में रहेगा।

घर में भी होगी चार्ज

टिगोर ईवी में दो चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। पहला फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, जो चार्जिंग स्टेशन पर कम समय में बैटरी को चार्ज करने में सक्षम है। वहीं दूसरा एसी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से इसको घर से भी चार्ज किया जा सकता है।

फीचर्स और खासियत

सुविधा और विशेषताएं इलेक्ट्रिक टिगोर स्टैंडर्ड टाटा टिगोर सिडैन पर आधारित है। इस इलेक्ट्रिक कार के दोनों वेरियंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स हैं। इसके साथ ही कार में डुअल एयरबैग (एक्सई+ वेरिएंट के साथ केवल ड्राइवर एयरबैग) और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) मिलेगा।

मिलेगी तीन साल की वारंटी

कार में तीन साल इनबिल्ट या फिर 1.25 लाख किमी की वारंटी दी गई है। यानी अगर तीन साल या 1.25 लाख किमी से पहले कोई समस्या आती है तो कंपनी गड़बड़ी को ठीक कर देगी।

बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक गाड़ियां

गाड़ी	एक चार्ज में तय दूरी	कीमत
हुंदै कोना इलेक्ट्रिक	452 किलोमीटर	23.04 से 28.07 लाख
महिंद्रा ई-वेरिटो	110 किलोमीटर	10.39 से 10.94 लाख
महिंद्रा ई2ओप्लस	99.90 किलोमीटर	8.51 से 9.36 लाख
टाटा टिगोर ईवी	213 किलोमीटर	9.44 लाख से शुरू

भरपूर माइलेज देती है मारुति सुजुकी की सियाज, जानिए इस गाड़ी यह है खास

अधिकांश लोगों को लगता है कि सेडान गाड़ियां चूंकि प्रीमियम रेंज वाली गाड़ियां होती हैं तो शायद यह कम माइलेज देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मारुति सुजुकी की सियाज तो माइलेज के मामले में काफी बेहतर है और लोग इसे इसी वजह से पसंद भी करते हैं।

इस गाड़ी से जुड़ी कुछ खास बातें

- सियाज में इंजन के तीन ऑप्शन हैं। पहला है, पेट्रोल बेस्ड के15 स्मार्ट हाईब्रिड 1462 सीसी वाला जो 6000 आरपीएम पर 77 किलोवाट की पावर और 4000 आरपीएम पर 138 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है।
- दूसरा ऑप्शन है DDis 225 डीजल बेस्ड इंजन।1498 सीसी का ये इंजन 4000 आरपीएम पर 70 किलोवाट की पावर और 1500-2500 आरपीएम पर 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है।
- तीसरा ऑप्शन है डीजल बेस्ड DDis 200 स्मार्ट हाईब्रिड 1248 सीसी इंजन। ये इंजन 4000 आरपीएम पर 66 किलोवाट की पावर और 1750 आरपीएम पर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है।
- अब बात माइलेज की। आपको बता दें कि पेट्रोल बेस्ड के15 स्मार्ट हाईब्रिड 1462 सीसी वाला इंजन 20 से 22 किलो मीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। वहीं DDis 225 डीजल बेस्ड इंजन करीब 27 KMPL और डीजल बेस्ड DDis 200 स्मार्ट हाईब्रिड 1248 सीसी इंजन करीब 28 KMPL का माइलेज देता है।
- इस गाड़ी के बाकी फीचर्स भी बेहतरीन हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस गाड़ी में फ्रंट में वेंटिलेटिड डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो इस कार में फ्रंट में सस्पेंशन सिस्टम भी काफी अच्छा है।
- सुरक्षा के लिहाज से इस गाड़ी में Front Fog Lamps हैं, Rear Defogger है, Reverse Parking Sensor है, Reverse Parking Camera है और Anti-theft Security System भी है।

Tata Nexon EV

साल 2020 की शुरुआती में होगी लॉन्च, यह होगी कीमत

टाटा मोटर्स ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नेक्सन ईवी पेश करेगी। इस कार की कीमत 15 से 17 लाख रुपए के बीच में होने का अनुमान है। कंपनी ने कहा कि इस वाहन में उसकी हाल ही में पेश जिपट्रॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मॉडल ईवी बाजार की मौजूदा रुकावटों को दूर करेगा और जीरो इमिशन के साथ सड़क पर शानदार प्रदर्शन देगा।

कंपनी के अध्यक्ष (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार एवं कॉरपोरेट रणनीति) शैलेश चंद्र ने बयान में कहा कि ''हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि नेक्सन ईवी देश में खरीदारों के लिए चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही से उपलब्ध हो जाएगा।''चंद्र ने कहा कि हमें भरोसा है कि नया नेक्सन ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों का मानक ऊंचा करेगा तथा इसे उपभोक्ताओं की पसंद बनाएगा।'' कंपनी ने कहा कि यह वाहन एक बार चार्ज करने पर करीब 300 किलोमीटर दौड़ सकता है।

क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी टाटा नैनो?

बीते 9 महीने से नहीं हुआ प्रोडक्शन

वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने इस साल के पहले नौ महीने में कम कीमत वाली अपनी नैनो कार की एक भी इकाई का उत्पादन नहीं किया है। कंपनी ने फरवरी में केवल एक इकाई की बिक्री की थी। हालांकि टाटा मोटर्स ने आधिकारिक रूप से इस मॉडल को बंद करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है।

कंपनी अब तक कहती रही है कि नैनो के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि टाटा मोटर्स यह स्वीकार करती है कि नैनो का मौजूदा रूप नए सुरक्षा नियमन और भारत चरण-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं कर पाएगा। यह लगातार नौवां महीना है, जब टाटा मोटर्स ने नैनो की एक भी इकाई का उत्पादन नहीं किया। कंपनी ने 2008 में नैनो को पेश था।

होंडा दिवाली ऑफर्स

इन कारों पर मिल रही है 5 लाख रुपए तक की छूट

अगर आप इस दिवाली हुंडई की नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कंपनी के मुताबिक होंडा दीपावली के अवसर पर अपनी कारों पर आकर्षक ऑफर्स की पेशकश कर रही है, जिसके चलते आप हुंडई कार की खरीददारी पर पांच लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। हुंडई की किस पर कितनी छूट मिल रही है ये जानेंगे यहां..

होंडा अमेज

अमेज के एस एडिशन को छोड़कर सभी वेरिएंट पर कंपनी चौथे एवं पांचवे साल की अतिरिक्त वारंटी दे रही है, जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। अगर आप पुरानी कार से नई अमेज को एक्सचेंज करते हैं तो आप 30,000 रुपए के एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। अगर आप पुरानी कार को एक्सचेंज नहीं करते हैं तो कंपनी आपको अमेज सेडान पर 16,000 रुपए के मेंटेनेंस पैकेज की सुविधा देगी। होंडा अमेज एस एडिशन पर या तो आप 16,000 रुपए का मेंटेनेंस पैक या फिर 30,000 रुपए के एक्सचेंज ऑफर का फायदा ले सकते हैं। आपको बतां दें कि एस एडिशन पर इन में से केवल एक बार में एक ऑप्शन को चुन सकते हैं।

होंडा जैज

जैज के सभी वेरिएंट पर कंपनी 50,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। जिन में 25,000 रुपए का नकद डिस्काउंट और 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

होंडा डब्ल्यूआर-वी

डब्ल्यूआर-वी पर कंपनी 25,000 रुपए का नकद डिस्काउंट और 20,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर दे रही है। इस कार पर आप 45,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं।

होंडा सिटी

सिटी सेडान पर आप कुल 62,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। इसके सभी वेरिएंट पर कंपनी 32,000 रुपए की छूट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बेनेफिट दे रही है।

होंडा बीआर-वी

इस कार पर कंपनी 35,000 रुपए का नकद डिस्काउंट और 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। इसके साथ ही कंपनी इस गाड़ी पर 26,500 रुपए की फ्री एक्सेसरीज भी मुहैया करा रही है। अगर आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा नहीं लेते हैं तो आपको 36,500 रुपए की फ्री एक्सेसरीज मिलेगी।

होंडा सिविक

सिविक के ऑफर को कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसके सभी डीजल वेरिएंट पर कंपनी 2.5 लाख रुपए तक की नकद छूट दे रही है। इस कार पर कंपनी 52 फीसदी प्राइस पर बायबैक की गारंटी दे रही है, जो 36 महीने या 75,000 किलोमीटर तक मान्य है। सिविक के टॉप जेडएक्स डीजल मैनुअल वेरिएंट की बायबैक प्राइस 11,62,148 रुपए है। चुनिंदा कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल इस कार को अपनी सुविधा के अनुसार 3, 4 या पांच साल के लिए लीज पर भी ले सकते हैं। सिविक के पेट्रोल वी सीवीटी वेरिएंट पर कंपनी 2.50 लाख रुपए की नकद छूट और यही लीज ऑप्शन दे रही है। वीएक्स और जेडएक्स पेट्रोल सीवीटी वेरिएंट पर 75,000 रुपए का नकद डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर और लीज ऑप्शन की पेशकश कर रही है।

होंडा सीआर-वी

सीआर-वी पर आप सबसे ज्यादा बचत कर सकते हैं। इसके डीजल एडब्ल्यूडी 9एटी वेरिएंट पर कंपनी पांच लाख रुपए तक का नकद डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा कंपनी इस कार पर 52 फीसदी प्राइस पर बायबैक की गारंटी भी दे रही है, जो 36 महीने या 75,000 किलोमीटर तक मान्य है। सीआर-वी डीजल एडब्ल्यूडी 9एटी वेरिएंट की बायबैक प्राइस 17, 04, 041 रुपए है। सीआर-वी 2डब्ल्यूडी 9एटी वेरिएंट पर आप चार लाख रुपए की नकद बचत कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कंपनियों में बढ़ी दिलचस्पी, BMW साल 2021 में लाएगी इलेक्ट्रिक कार 'I-1"

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सड़कों पर चलने वाली वाहनों की तकनीक में भी बदलाव करना जरूरी हो गया है। फॉसिल फ्यूल को लेकर वाहनों की निर्भरता को कम करने के लिए देश-विदेश में मुहिम युद्ध स्तर पर छेड़ दी गई है। जहां तक इस ईंधन के इतर बात करें तो बायो डीजल को लेकर भी कई देश की सरकारों ने कमर कस ली है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि वाहनों को इलेक्ट्रिक पर भी निर्भर कराया जाए।

लग्जरी कारें बनाने वाली जर्मनी की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू 2021 तक एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपनी 1 सीरीज की हैचबैक बीएमडब्ल्यू आई-1 इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारेगी।

ऑटो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि आई-1 एक शुरुआती वर्ग (एंट्री लेवल) कार होगी, जो पारंपरिक गैसोलीन कार की तरह दिखाई देगी। बीएमडब्ल्यू की ओर से आई-1 को जल्द से जल्द 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में लचीला रुख अपनाए हुए है कि वह किन मॉडलों को इलेक्ट्रिक के तौर पर आगे बढ़ा सकती है। ऑटो निर्माता की रणनीति पारंपरिक रूप से संचालित अपने समकक्षों के समान इलेक्ट्रिक कारों की अपनी श्रेणी को मजबूत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक-1 सीरीज को ब्राइट बॉडीवर्क और एक आकर्षक फ्रंट ग्रिल के साथ पेश किया जाएगा।

मिड रेंज की इलेक्ट्रिक कारों में रेनॉ की धमक

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनॉ (Renault) ने भी कमर कस ली है। रेनॉल्ट अब 2022 तक भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना चाहती है। रेनॉ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा कि कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन कथित रूप से किफायती या बड़े बाजार सेग्मेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। रेनॉ ने कहा कि यह हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, बल्कि, कंपनी सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर किफायती वाहनों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है।

अयोध्या मामले में हिन्दू पक्षकार ने सुप्रीमकोर्ट से कहा, बाबर की ऐतिहासिक भूल सुधारने की जरूरत है

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में हिन्दू पक्ष ने दलील दी कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करके मुगल शासक बाबर द्वारा की गयी 'ऐतिहासिक भूल' को अब सुधारने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष एक हिन्दू पक्षकार की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन ने कहा कि अयोध्या में अनेक मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम इबादत कर सकते हैं लेकिन हिन्दू भगवान राम का जन्म

स्थान नहीं बदल सकते। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य के वाद में प्रतिवादी महंत सुरेश दास की ओर से बहस करते हुये परासरन ने कहा कि सम्राट बाबर ने भारत पर जीत हासिल की और उन्होंने खुद को कानून से ऊपर रखते हुये भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करके ऐतिहासिक भूल की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। संविधान पीठ ने परासरन से परिसीमा के कानून, विपरीत कब्जे के सिद्धांत और अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि से मुस्लिमों को बेदखल किये जाने से संबंधित अनेक सवाल किये। पीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या मुस्लिम अयोध्या में कथित मस्जिद छह दिसंबर, 1992 को ढहाये जाने के बाद भी विवादित संपत्ति के बारे में डिक्री की मांग कर सकते हैं? पीठ ने परासरन से कहा कि वे कहते हैं, एक बार मस्जिद है तो हमेशा ही मस्जिद है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं।

इस पर परासरन ने कहा कि नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं कहूंगा कि एक बार मंदिर है तो हमेशा ही मंदिर रहेगा। पीठ ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार यह दलील दे रहे हैं कि संपत्ति के लिये वे डिक्री का अनुरोध कर सकते हैं भले ही विवाद का केन्द्र भवन इस समय अस्तित्व में नहीं हो। पीठ द्वारा परासरन से अनेक सवाल पूछे जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि धवन जी, क्या हम हिन्दू पक्षकारों से भी पर्याप्त संख्या में सवाल पूछ रहे हैं?

प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सोमवार को आरोप लगाया था कि सवाल सिर्फ उनसे ही किये जा रहे हैं और हिन्दू पक्ष से सवाल नहीं किये गये। संविधान पीठ अयोध्या विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर मंगलवार को 39वें दिन भी सुनवाई कर रही थी।

पूरा देश गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने की तैयारी में है: मोदी

■ थानेसर/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र सरकार सिख गुरु गुरु नानक देव की 550वीं जयंती विश्वभर में मनाने के लिए सभी प्रबंध कर रही है। प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के पहले यहां एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा,''पूरा देश गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने की तैयारी में है और केन्द्र इसे विश्वभर में मनाने का इंतजाम कर रहा है।''

उन्होंने कहा,''मुझे प्रसन्नता है कि

करतारपुर थलियारा(परियोजना) पूरा होने वाला है।'' मोदी ने अपनी रैली में कहा कि उनकी सरकार को सात दशक पहले हुई 'राजनीतिक और रणनीतिक गलती' को काफी हद तक सुधारने का अवसर मिला। उन्होंने कहा,''मुझे उम्मीद है कि प्रकाशपर्व उल्लास लाएगा।'' गौरतलब है कि करतारपुर गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के डेरा बाबा नानक से जोड़ेगा।

यह गलियारा गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। मोदी ने राफेल सौदे का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,''पता नहीं कांग्रेस नेताओं को क्या हो जाता है। देशवासियों को खुशी देने वालों मुद्दों पर वे परेशान हो जाते हैं।''

पीएमसी बैंक ग्राहक की हार्ट अटैक से मौत, बैंक में फंसे थे 90 लाख

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से जुड़ा मामला इन दिनों सुर्खियों में लगातार बना है। जिसको लेकर खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस बीच एक पीएमसी बैंक के खाताधारक की मौत हो गई। ओशिवारा के तारापोरेवाला गार्डन में रहने वाले संजय गुलाटी का पीएमसी बैंक में करीब 90 लाख रुपया जमा है। सोमवार को वह बैंक पर लगाई गई

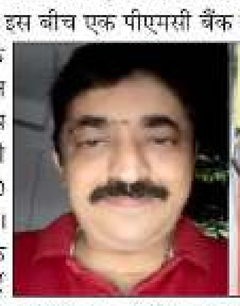

पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्हें हार्ट अटैक आया। जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। बता दें कि पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नकदी निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं।

मंत्रियों के टिकट काटे जाने पर बोले नड्डा, हम भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के प्रति हैं संवेदनशील

■ मुंबई/ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों का टिकट काटा जाना यह दिखाता है कि पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के प्रति 'संवेदनशील' है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट देने से मना कर दिया गया है।

इन नेताओं में एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बवानकुले और प्रकाश मेहता शामिल हैं। इनमें से तावड़े और बवानकुले देवेंद्र फड़णवीस सरकार की कैबिनेट में क्रमशः शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री हैं। खड़से एवं मेहता ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद क्रमशः राजस्व और आवास मंत्री के से इस्तीफा दे दिया था।

चार मंत्रियों का टिकट काटे जाने के बारे में पूछे जाने पर नड्डा ने कहा

कि यह दिखाता है कि हम भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के प्रति संवेदनशील हैं। पार्टी ने कदम उठाये हैं। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के सख्त रुख को दर्शाता है।

हमारा फैसला भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी संकल्प और हमारी ईमानदार मंशा को रेखांकित करता है। पार्टी घोषणापत्र जारी किये जाने के बाद वह यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि कुछ दागी नेता विपक्ष से भाजपा में शामिल हुए हैं और उनमें से कुछ को टिकट दिया गया है तो नड्डा ने कहा कि भाजपा अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर भाजपा का रुख स्पष्ट है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मौजूदा रुख पर आगे बढ़ेंगे।

करतारपुर गलियारे के निर्माण कार्य हर हाल में 31 अक्तूबर तक होगा मुकम्मल-विजय इंदर सिंगला

लोक निर्माण मंत्री ने डेरा बाबा नानक में गलियारे के चल रहे काम का जायजा लिया

■ चंडीगढ़ /डेरा बाबा नानक/ब्यूरो

पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर खुल रहे करतारपुर गलियारे के निर्माण काम का जायजा लेने मंगलवार को डेरा बाबा नानक पहुँचे लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने कहा भारत वाले हिस्से का निर्माण कार्य हर हाल में 31 अक्तूबर तक मुकम्मल हो जायेगा। श्री सिंगला ने भारत -पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद पर ज़ीरो लाईन पर चल रहे काम समेत सड़कों, पुलों, इंटीग्रेटिड चैक पोस्ट (आई.सी.पी.) आदि के काम का जायजा लेते हुए संतुष्टि ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 से 31 अक्तूबर के बीच सभी काम मुकम्मल करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था और आज ज़मीनी स्तर पर देखने के उपरांत तसल्ली हुई। श्री सिंगला ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सरहद पर पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने वाला पुल भारत वाले तरफ़ पर तो बन गया है परन्तु अभी पाकिस्तान वाला पुल नहीं बना। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों पुल आपस में नहीं जोड़े जाते तब तक भारत

वाला पुल बंद रहेगा और परिवर्तनीय प्रबंध के तौर पर रास्ता रखा गया है जिसके द्वारा श्रद्धालुओं को अंतरराष्ट्रीय सरहद पार गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि डेरा बाबा नानक में श्रद्धालुओं की बड़ी आमद को देखते हुए इस ऐतिहासिक कस्बे को जोड़ती सड़कों की अपग्रेडेशन का काम भी तय समय के अंदर मुकम्मल कर लिया जावे। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बटाला -डेरा बाबा नानक रोड 3.05 करोड़ रुपए की लागत के साथ 7 से 10 मीटर तक 2.10 किलोमीटर, रमदास -डेरा बाबा नानक रोड 3.60 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5.5 /7 से 10 मीटर तक 3.10 किलो मीटर, फतेहगढ़ चूड़ीयां -डेरा बाबा नानक रोड 1.49 करोड़ रुपए की लागत के साथ 900 मीटर चौड़ी हो रही है। श्री सिंगला ने कहा कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए 13 करोड़ नानक नाम लेवा संगत कई वर्षों से अरदास कर रही थी जिसको अब वह पूरा होते हुए देख रहे हैं।

स्कूली बच्चे अब किसानों को धान की पराली न जलाने के लिए जागरूक करेंगे

ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते समूह स्कूलों के विद्यार्थी 18 अक्तूबर को प्रातःकाल 9 से 10 बजे तक निकालेंगे जागरूक मार्च-काहन सिंह पन्नू

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशों पर पंजाब सरकार द्वारा धान की पराली जलाने के खिलाफ़ शुरु की गई मुहिम में अब पंजाब के स्कूली बच्चे भी अपना योगदान डालेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते राज्य के समूह प्राइमरी, मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थी 18 अक्तूबर को अपने-अपने क्षेत्रों के गाँवों में प्रात:काल 9 से 10 बजे तक जागरूकता रैलियों के द्वारा किसानों को पराली जलाने के बुरे प्रभावों से अवगत करवाएंगे।

इस संबंधी जानकारी देते हुए कृषि विभाग के सचिव श्री काहन सिंह पन्नू ने बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा बीते दिन पंजाब के प्रगतिशील किसानों के साथ मीटिंग की गई थी जिसमें उन्होंने पराली न जलाने वाले किसानों के सुझाव सुने। इसके बाद यह फ़ैसला लिया गया कि पराली न जलाने की मुहिम को पूर्णत: सफल बनाने के लिए जागरूकता सबसे अहम हथियार है जिसके लिए स्कूली बच्चे सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा के सचिव, समूह डिप्टी कमीश्नरों को पत्र लिखकर 18 अक्तूबर को निकाली जाने वाली रैलियों के लिए पराली जलाने के बुरे प्रभावों संबंधी जानकारी मुहैया करवाई गई है वहीं यह भी बताया गया कि किस तरह पराली न जला कर भूजल को बचाने, उत्पादन बढ़ाने और सबसे अहम हमारे वातावरण को कैसे बचाया जा सकता है। सरकार द्वारा डिप्टी कमीश्नरों और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पराली न जलाने के स्लोगन भी स्कूलों को मुहैया करवाए गए हैं। इसके साथ ही पराली जलाने से होने वाले धरती के खाद्य तत्वों के नुकसान और वातावरण में फैलती गंदली गैसों संबंधी भी जानकारी मुहैया करवाई गई है।

श्री पन्नू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धान की पराली को आग लगाने से रोकने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में किसानों को सब्सिडी पर मशीनें मुहैया करवाने के साथ-साथ उनको पराली जलाने से वातावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभावों संबंधी भी अवगत करवाया जा रहा है। पंजाब में बहुत किसान ऐसे हैं जो पराली को आग लगाए बिना ही खेतों को जोत कर गेहूँ की फसल की बिजाई या सब्जियाँ आदि की काश्त करके बढ़िया उत्पादन प्राप्त करते हैं।

धान की पराली को आग लगाने से धरती की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है और इस आग के धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि नवबंर महीने में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। गुरू साहिब द्वारा पवन, पानी और धरती को साफ़ रखने के दिए संदेश को अमली रूप में लागू करने के लिए स्कूली विद्यार्थी अहम रोल निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूलों में 60 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रदूषित होते जा रहे वातावरण का सबसे बड़ा नुकसान इन बच्चों और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों के बच्चे अब खुद जागरूक मुहिम की कमान संभालते हुए वातावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान परिवारों के बच्चों को कहा जायेगा कि वह अपने माँ बाप के साथ संवाद रचा कर उनको पराली न जलाने के लिए मनाएं और साथ ही बच्चों को प्रेरित किया जाये कि वह दीवाली के समय पटाखे न चला कर वातावरण साफ़ रखने के लिए प्रण लें।

सी.बी.आई. मुझे अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है: चिदंबरम

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत का अनुरोध करते हुये मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि सीबीआई सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिये ही हिरासत में रखना चाहती है। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान या धन हड़पने जैसा भी कोई आरोप नहीं है। दोनों अधिवक्ताओं ने कांग्रेस नेता की जमानत रद्द करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले के निष्कर्षों पर भी सवाल उठाये और कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय उसे मामले के गुण दोषों में नहीं जाना चाहिए था।

न्यायालय ने कहा कि वह बुधवार को जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनेगा। पूर्व वित्त मंत्री ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है। चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें लगातार जेल में बंद रखना 'सजा के रूप' में है और अज्ञात तथा अपुष्ट आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बीच, निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की आईएनएक्स धन शोधन मामले में चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दे दी और कहा कि यदि जरूरी हो, तो जांच एजेन्सी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चिदंबरम को जमानत देने से इंकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को सोमवार को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के इस नेता के भागने का खतरा नहीं है और वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनके भागने के खतरे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना के पहलू चिदंबरम के पक्ष में जबकि गवाहों को प्रभावित करने संबंधी तीसरा बिन्दु उनके खिलाफ जाता है। सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था और इस समय वह 17 अक्टूबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं। जांच ब्यूरो ने वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रूपए के निवेश की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में ही धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

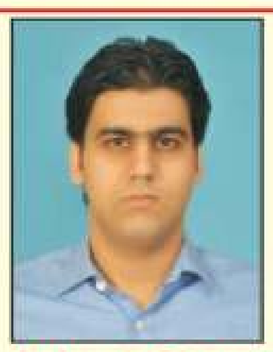

Ankush Sharma

Chartered Engineer

Alumni M.S.(Software Engineering), BITS Pilani

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin